भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2228

दिनांक 11 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

मिशन पोषण 2.0

2228. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी और अर्ध-शहरी बच्चों में उच्च वसा, चीनी और नमक (एचएफएसएस) वाले खाद्य पदार्थों के बढ़ते सेवन से उत्पन्न ''छिपी हुई भूख" से निपटने के लिए मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के समन्वय से, अति-प्रसंस्कृत स्नैक्स में ''खाली कैलोरी" की पहचान करने के लिए ''फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग" (एफओपीएल) जागरुकता अभियान विकसित कर रहा है;

(ग) बौनापन और दुर्बलता जैसे पारंपरिक मापदंडों के साथ-साथ ''जीवनशैली कुपोषण" (अधिक वज़न/मोटापा) की निगरानी के लिए पोषण ट्रैकर ऐप को कैसे उन्नत किया जा रहा है; और

(घ) फास्ट-फूड पर निर्भरता से उत्पन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटने के लिए ''जैविक रूप से समृद्ध" प्राकृतिक विकल्पों को बढ़ावा देने हेतु स्कूलों में ''पोषण वाटिका" पहल की प्रगति क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ): 'छिपी हुई भूख' आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दर्शाने वाला शब्द है। आईसीएमआर-राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार, उच्च वसा, नमक और चीनी (एचएफएसएस) वाले खाद्य पदार्थ वे खाद्य पदार्थ हैं जो खाना पकाने के लिए प्रयुक्त अत्यधिक तेल/वसा या अधिक चीनी और नमक मिलाकर तैयार किए जाते हैं।

मंत्रालय में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के समन्वय से अति-प्रसंस्कृत स्नैक्स में "एम्प्टी कैलोरी" का पता लगाने के लिए "फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग" (एफओपीएल) जागरूकता अभियान तैयार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

महिलाओं और बच्चों में उच्च वसा, चीनी और नमक (एचएफएसएस) वाले खाद्य पदार्थों के सेवन को कम करने के लिए मंत्रालय द्वारा की गई पहलें इस प्रकार हैं:

- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को दिए जाने वाले पूरक पोषण (घर ले जाने वाला राशन और पका हुआ गर्म भोजन) में चीनी के अधिक उपयोग को कम करें।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी आयु वर्ग के लोगों में एचएफएसएस युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें और खाद्य तेलों, विशेष रूप से सेचुरेटेड वसा का सेवन कम करने को बढ़ावा दें और ट्रांस वसा के उपयोग से बचें।
- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जमीनी कार्यकर्त्रियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आम जनता के लिए स्वस्थ जीवनशैली और संतुलित आहार पर लक्षित अभियान चलाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। इस दिशा में एक अभिनव पहल **आंगनवाड़ी केंद्रों, सरकारी कार्यालयों, बाल देखरेख संस्थानों, राशन की दुकानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर तेल और चीनी बोर्ड लगाना है।** इन बोर्डों का उद्देश्य आहार संबंधी विकल्पों पर चर्चा को बढ़ावा देना और परिवारों को आमतौर पर खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में छिपी चीनी और तेल की मात्रा के प्रति जागरूक करना है।
- राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान जन आंदोलन के अंतर्गत नियमित जागरूकता अभियान चला रहे हैं और उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले पोषण पखवाड़े (8-22 अप्रैल 2025) और पोषण माह (17 सितंबर-16 अक्टूबर 2025) के दौरान देश भर में चलाए गए अभियान स्वस्थ जीवनशैली, बाल्यावस्था के मोटापे की रोकथाम और चीनी एवं तेल का उपयोग कम करने जैसे विषयों पर केंद्रित थे। इन सभी अभियानों में लोगों की भागीदारी की जानकारी पोषण ट्रैकर के जन आंदोलन डैशबोर्ड पर उपलब्ध है।पोषण अभियान के तहत वर्ष 2018 से आयोजित पिछले जन आंदोलन अभियानों में 150 करोड़ से अधिक गतिविधियां दर्ज की गई हैं।

पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन में ठिगनेपन, दुबलेपन और अल्प वजन श्रेणियों के अलावा अधिक वजन/मोटापे से ग्रस्त बच्चों की पहचान और निगरानी की व्यवस्था है।

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण निम्नलिखित जागरूकता उपाय करता है:

- 'ईट राइट इंडिया' अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं में स्वस्थ खान-पान की आदतों को बढ़ावा देना है।
- 'आज से थोड़ा कम' अभियान उपभोक्ताओं को आहार में बदलाव के माध्यम से वसा, नमक और चीनी का सेवन धीरे-धीरे कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- "मोटापा रोकें" और "मोटापे से लड़ें" के विषय में सोशल मीडिया अभियान।

- बच्चों को मोटापे के खतरों और स्वस्थ खानपान तथा नियमित शारीरिक गतिविधि के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए बच्चों के अनुकूल एनिमेटेड वीडियो तैयार किए जाते हैं और सोशल मीडिया पर प्रकाशित किए जाते हैं।
- 'ईट राइट इंडिया' अभियान के अंतर्गत "#हर लेबल कुछ कहता है" जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को लेबल की जानकारी देकर उन्हें सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। इसका लक्ष्य उपभोक्ताओं को पोषण संबंधी जानकारी (कैलोरी, वसा, शर्करा, प्रोटीन, सर्विंग साइज), सामग्री की सूची, एलर्जी संबंधी चेतावनी और तारीख का उल्लेख (डेट मार्किंग) जैसी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जागरुक करना है।

प्रधानमंत्री पोषण योजना के दिशानिर्देशों में विद्यालय पोषण उद्यान (एसएनजी), जिसे किचन गार्डन भी कहा जाता है, बनाने की सिफारिश की गई है ताकि बच्चे अपना भोजन स्वयं उगाना सीख सकें। दिनांक 31 मार्च, 2025 तक इस योजना के तहत 6.28 लाख से अधिक विद्यालयों में पोषण उद्यान बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा, देश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में मिशन पोषण 2.0 के तहत पोषण वाटिकाएं स्थापित की जा रही हैं ताकि स्थानीय और मौसमी फलों तथा सब्जियों के सेवन को प्रोत्साहित किया जा सके, जिससे आहार विविधता में सुधार हो और सूक्ष्म पोषक तत्वों का सेवन बढ़े। फरवरी 2026 तक आंगनवाड़ी केंद्रों में कुल 3,18,176 पोषण वाटिकाएं बनाई जा चुकी हैं।

*****